

आजाद सिपाही

रांची, 04 मार्च, 2023, शनिवार, वर्ष 08, अंक 135 फाल्गुन, शुक्ल पक्ष,

द्वादशौ, संवत् 2079, पृष्ठ : 12, मूल्य : ₹3.00



झारखंड विधानसभा में वर्ष 2023-24 के लिए 1,16,418 करोड़ का बजट पेश ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि पर विशेष जोर

सरकार ने सभी वर्गों को साधने की कोशिश की

आजाद सिपाही संवाददाता

रांची। झारखंड विधानसभा में शुक्रवार को वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया। बजट में सरकार की ओर से कई नयी योजनाओं की घोषणा की गयी है। इस बजट में युवाओं को रोजगार के अलावा किसानों और महिलाओं के लिए भी कई बड़ी घोषणा की गयी। बजट में ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि पर विशेष जोर दिया गया है। वित्त मंत्री ने सदन में वित्तीय वर्ष 2023-24 में एक लाख 16 हजार 418 करोड़ का बजट पेश किया। इसमें राजस्व व्यय के लिए 84 हजार 87 सौ 76 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं, जबकि पूंजीगत व्यय के तहत 31 हजार 742 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है। सदन में बजट प्रस्तुत करने के बाद वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वर्ष 2022-23 के लिए 'हरम अपन बजट' पोर्टल के माध्यम से एक नवाचारी प्रयोग प्रस्तुत किया गया था, जिसमें झारखंडवासियों की उत्पादकता बढ़ाने का भागीदारी हुई थी। आम लोगों के सुझाव से योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए वर्ष 2023-24 योजना क्रियान्वयन वर्ष होगा।



बजट में की गयी 15 फीसदी बढ़ोतरी

वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि अब तक जितने भी बजट पेश किये गये हैं, उसमें सामान्य तौर पर 10 प्रतिशत की वृद्धि होती थी, लेकिन हमने बजट में 15 प्रतिशत की वृद्धि की है। उन्होंने कहा कि समान्य प्रश्न के लिए 33,378.45 करोड़ रुपये, सामाजिक प्रश्न के लिए 43,303.44 करोड़ रुपये और आर्थिक प्रश्न के लिए 39,736.11 करोड़ रुपये हैं। राजकोषीय घाटा भी 11,674.57 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। बजट बढ़ा तो है, लेकिन लोक ऋण नहीं बढ़ाया गया है। यह पूर्व की तरह 18 सौ रुपये ही रहने की संभावना है।

योजनाओं पर किया गया है फोकस

वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने हर क्षेत्र को बजट आवंटित किया है, लेकिन सरकार का जोर स्थापना से ज्यादा योजनाओं पर है। राज्य सरकार ने इन्फ्रास्ट्रक्चर से लेकर कृषि तक को फोकस करते हुए योजनाएं लागू करने को लेकर बजट फोकस किया है। इसके तहत सिंचाई व्यवस्था और जल संरक्षण के लिए पांच एकड़ से कम क्षेत्र वाले तालाबों का मशीन से गाद हटाने और डीप बोरिंग कराने पर पांच सौ करोड़ रुपये खर्च करने पर जोर दिया गया है। सौर ऊर्जा आधारित माइक्रो लिफ्ट इरीगेशन के लिए कृषि समृद्धि योजना लागू की जायेगी।

हर सेक्टर को आगे बढ़ाने की है बात

वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने कहा कि बजट में हर क्षेत्र को आगे बढ़ाने की बात कही गयी है। बजट में श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के लिए 67 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है। श्रम नियोजन के लिए 985 करोड़ का बजट प्रस्तावित है। वहीं मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत राज्य के 1.40 लाख युवक-युवतियों को कौशल प्रशिक्षण दिये जाने का लक्ष्य रखा गया है। इस बजट में वित्त मंत्री के मुताबिक राज्य में आधारभूत संरचनाओं का विकास तेजी से करना सरकार की प्राथमिकता है। राज्य के आर्थिक स्वास्थ्य को बेहतर करने और भविष्य की पीढ़ी को आर्थिक बौद्धिक विरासत से बचाने के लिए बेहतर ऋण प्रबंधन किया गया है। बजट में राजस्व व्यय के लिए 84 हजार 676 करोड़ और पूंजीगत व्यय के लिए 31 हजार 742 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है।

तीन सालों में राज्य की स्थिति मजबूत हुई है

डॉ रामेश्वर उरांव ने कहा कि योजना की राशि में तीन गुना वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। तीन सालों में राज्य की स्थिति मजबूत हुई है। राजस्व आय में सरकार ने वृद्धि की है। बजट में कई नयी घोषणाएं की गयी हैं। इसके तहत 1.40 लाख युवक-युवतियों को कौशल प्रशिक्षण दिए जाने का लक्ष्य है। प्रशिक्षण के बाद रोजगार नहीं मिलने पर छह महीने तक युवाओं को एक हजार और युवतियों-दिव्यांगों को डेढ़ हजार रुपये दिये जायेंगे। वर्ष 2023-24 में मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का विस्तारीकरण करते हुए दो लाख युवाओं तक लाभ पहुंचाने की योजना है। इसके अलावा मानकी-मुंडा शासन व्यवस्था के तहत मानकी, मुंडा, इकुआ की न्यायिक, प्रशासनिक और वित्तीय कार्य में भूमिका को देखते हुए उन्हें दोपहिया वाहन उपलब्ध कराया जायेगा। अगले वर्ष में कृषि समृद्धि योजना लागू की जायेगी। वर्ष 2023-24 में एफपीओ के अनुदान में 50 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं। फसल सुरक्षा कार्यक्रम नामक एक नयी योजना की शुरुआत की गयी है। गिरिडीह और जमशेदपुर में नये डेयरी प्लांट और रांची में मिल्क पाउडर प्लांट के साथ मिल्क प्रोडक्ट प्लांट की स्थापना के लिए 180 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है। दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से गठबंधन सरकार द्वारा एक रुपये प्रति लीटर की दर से प्रोत्साहन राशि देने की योजना शुरू की गयी थी, जिसे वर्ष 2022-23 में बढ़ाकर दो रुपये कर दिया गया था। वर्ष 2023-24 में इसे दो रुपये से बढ़ाकर तीन रुपये करने की घोषणा की गयी।

बजट की मुख्य बातें और घोषणाएं

- गिरिडीह एवं जमशेदपुर में नये डेयरी प्लांट तथा रांची में मिल्क पाउडर प्लांट एवं मिल्क प्रोडक्ट प्लांट की स्थापना
- दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन राशि दो रुपये से बढ़ाकर तीन रुपये करने की घोषणा
- लैप्स / पैक्स की भंडारण क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से वर्ष 2023-24 में 100 एमटी क्षमता के कुल 566 एवं 500 एमटी क्षमता के 146 नये गोदामों का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है
- बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन मिशन नामक नयी योजना शुरू होगी
- पटमदा और पलामू में मागा लिफ्ट सिंचाई परियोजनाएं होंगी शुरू
- पंचायत सचिवालय सुदृढीकरण योजना होगी शुरू
- पंचायत ज्ञान केंद्र की स्थापना की जायेगी
- महिला एवं किशोरी कल्याण योजना होगी शुरू
- आंगनवाड़ी चलो अभियान योजना की होगी शुरुआत
- 800 नये आंगनवाड़ी भवन के निर्माण होगा।
- आंगनवाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं का मानदंड बढ़ेगा
- नेतरहाट विद्यालय की तर्ज पर चाइबासा, दुमका तथा बोकारो में खुलेंगे स्कूल
- बरही, बूँद, पतरात, चाइबासा, जमशेदपुर एवं नॉलिंग सिटी, खूटी में नये राजकीय पॉलिटेक्निक खोले जायेंगे
- बोकारो एवं रांची में मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी
- पलामू, चाइबासा एवं दुमका में मनोचिकित्सा केंद्र की स्थापना होगी
- मानकी, मुंडा, इकुआ को दोपहिया वाहन देगी सरकार
- अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं को निःशुल्क आवास की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग, धनबाद, देवघर, बोकारो, चाइबासा आदि प्रमुख शहरों में बहुमंजिला छात्रावासों के निर्माण होगा
- साहेबगंज-बरहेट-जामताड़ा-दुमका-गोविंदपुर एडीबी पथ का फोरलेन में उन्नयन होगा
- कोडरमा-जमुआ गिरिडीह-टुंडी - गोविंदपुर पथ का फोरलेन में उन्नयन होगा
- सतसंग-भिरखीबाद पथ का फोरलेन में उन्नयन होगा
- राज्य के गांव में 3100 किमी सड़कें तथा 143 पुलों के निर्माण कार्य कराया जायेगा
- आगामी वित्तीय वर्ष में दुमका तथा बोकारो स्थित हवाई अड्डों से उड़ान प्रारंभ की घोषणा की गयी है
- साहेबगंज में हवाई अड्डा के लिए भूमि चिन्हित कर ली गयी है। जल्द ही इसके लिए भी एमओयू किया जायेगा
- आम जनता के लिए सस्ते दर पर एयर एंबुलेंस सेवा शुरू करने की बजट में घोषणा की गयी
- फ्लोटिंग सोलर प्लांट अधिष्ठापन हेतु गेतलसूद में पूर्व से स्वीकृत योजना के अतिरिक्त चाइल में भी पीपीपी मोड में प्लांट अधिष्ठापन का प्रस्ताव
- नये औद्योगिक क्षेत्र के निर्माण का भी प्रस्ताव है
- पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा, पेंशन कोष का होगा गठन।

FLORENCE
Group of Institutions
(A Unit of : Haji Abdur Razzaque Educational Society)
Irba, Ranchi-835219 (Jharkhand)

Admission OPEN 2023-24

PLACEMENT Assistance Scholarship Facility Available

NURSING PARAMEDICAL PHARMACY

ANXI GYM DRESSERS (ONLY) ECO POST (BASIC) B.S.C. X-BAY (OPHTHALMIC) BASIC (B.S.C.) M.S.C. ASST. OF ASSISTANT

Separate Hostel For Boys And Girls

M: 9031231082, 7903999411, 6205145470
E-mail: fairsiba@gmail.com
Website: www.florenceinirba.com

झारखंड के बजट पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा ऐतिहासिक, बेहतर और संतुलित बजट

आजाद सिपाही संवाददाता

रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बजट को ऐतिहासिक, बेहतर और संतुलित बताया है। विधानसभा परिसर में बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड की आम जरूरतों के अलावा, सवा तीन करोड़ जनता के अलावा यहां के कई संसाधनों पर भी सरकार का बजट जाता है। आपने देखा कि सामाजिक सुरक्षा को लेकर हमलोगों ने कई ऐतिहासिक कदम उठाये, लेकिन, इससे काम नहीं बनेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने



कहा कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। 20 सालों में सिर्फ बजट एक कागजी कार्रवाई के रूप में देखने को मिला, लेकिन, इस बजट का लाभ वर्तमान में आमलोगों को तो मिलेगी ही, आने वाली कई पीढ़ी को भी इसका लाभ

मिलेगा। सरकार ने झारखंड के आम लोगों के साथ-साथ यहां के संसाधनों का भी बजट में ध्यान रखा है। इस बार 'हमिन कर बजट' : सौंपने ने कहा कि पहले हम लोगों ने 'हमारा बजट' नाम दिया, मगर इस बार 'हमिन कर बजट' नाम दिया है। राज्य के हितों और समस्याओं का समाधान कैसे हो, इसे ध्यान में रखकर यह बजट तैयार किया गया है। पिछले वर्ष की तुलना में बजट में 15 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है। राज्य को आगे ले जाने के लिए और अधिक

संसाधनों की जरूरत होगी आने वाले समय में। आने वाले समय में इसका दूरगामी परिणाम दिखेगा। आगामी बजट में परिवर्तन दिखेगा। सरकार ने नौजवानों से पूछा - हम किस रास्ते पर चलें : मुख्यमंत्री ने नियोजन नीति पर कहा कि हमने राज्य के नौजवानों से पूछा कि किस रास्ते पर चलें। वर्तमान परिस्थिति को दुरुस्त करने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन, विकास की गति न धीमी होगी, न रुकेगी। इसी कड़ी में सारी चीजों को बेहतर करते हुए सरकार आगे बढ़ेगी।

'क्रियान्वयन वर्ष' की झलक बजट में दिख रही योजनाओं पर व्यय का फोकस

घोषणाएं धरातल पर उतरी, तो दिखेगा बदलाव

प्रशांत झा

रांची (आजाद सिपाही)। झारखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए शुक्रवार को बजट पेश कर दिया। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने चौथी बार बजट पेश किया। उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य लगातार प्रगति के पथ पर है। इस बार सरकार ने पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले 15 फीसदी अधिक का बजट पेश किया है। वित्तीय वर्ष 2023-2024 को सरकार ने 'क्रियान्वयन वर्ष' के रूप में घोषित किया है। बजट में इसकी झलक दिख रही है। बजट में पूंजीगत व्यय को बढ़ाया गया है, वहीं स्थापना व्यय को कम किया गया है, यानी अगर राशि योजनाओं पर सही-सही खर्च

होगी, तो निश्चय ही धरातल पर बहुत सी चीजें बदल जायेंगी। योजना व्यय में 24 फीसदी की बढ़ोतरी

सरकार ने योजना व्यय में 24 फीसदी की बढ़ोतरी की है। चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में योजना व्यय 57259 करोड़ रुपये था। वहीं आगामी वित्तीय वर्ष के लिए 70973 करोड़ रुपये हैं। पिछले तीन सालों में स्थापना और योजना व्यय का आकलन किया जाये, तो स्थापना व्यय में कमी आ रही है और योजना व्यय में लगातार वृद्धि हो रही है। यह विकास के लिए एक शुभ संकेत है। सरकार ने स्वास्थ्य, कृषि, बाल विकास, नागर विमानन समेत हर क्षेत्र में विकास योजनाओं को तरजीह दी है। राज्य में नये एयरपोर्ट बनाने की योजना है, तो छात्रों के लिए हॉस्टल और लाइब्रेरी भी बनेंगे। नये आंगनवाड़ी केंद्र भी बनेंगे, तो स्कूलों, आइटीआइ कॉलेजों आदि का जीर्णोद्धार भी होगा।

बजट तो बढ़ाया, लेकिन नहीं बढ़ेगा ऋण

सरकार ने एक लाख 16 हजार 418 करोड़ रुपये का बजट पेश किया है। इसमें राजस्व व्यय 84 हजार 676 करोड़ और पूंजीगत व्यय 31 हजार 742 करोड़ रखा गया है। बजट में खास बात यह है कि सरकार ने बजट आकार बढ़ाने के लिए ऋण का इस्तेमाल नहीं किया है, बल्कि अपने राजस्व को बढ़ाने की दिशा में कदम उठाती हुई दिख रही है। पूर्व के ऋण की राशि को नहीं बढ़ाया गया है। पिछले वित्तीय वर्ष की तरह ऋण राशि 18 हजार करोड़ रुपये ही रहेगी। सरकार ने राजस्व संग्रह पर भी बल दिया है। सरकार अपने स्रोत से 30 हजार 860 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। जहां तक राजकोषीय घाटा की बात है, तो वह 11674.57 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जो जीएएसडीपी का 2.76 फीसदी है।

सामाजिक प्रक्षेत्र पर भी ध्यान:

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार गरीब, आदिवासी, युवा, महिला, किसान आदि के उत्थान की चर्चा करते हैं। उनका फोकस इनके विकास पर है। बजट में उनकी बात परिलक्षित भी हो रही है। सरकार आगामी बजट में युवा, महिला, बुजुर्ग, किसान समेत हर वर्ग का ध्यान रखते हुए दिख रही है। सामाजिक प्रक्षेत्र के लिए 43303.44 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सरकार ने मानकी, मुंडा आदि को दुपहिया वाहन देने, ट्रेनिंग कर चुके बेरोजगार युवाओं को भत्ता देने, छात्रों को स्कॉलरशिप आदि की जो घोषणा बजट में की है, उसके लिए राशि का भी प्रावधान किया गया है। कुल मिलाकर बजट हर स्तर पर सटीक दिख रहा है। अब इसे विधानसभा से पारित होने और धरातल पर उतरने का इंतजार करना होगा।

यह बजट राज्य के विकास से कोसों दूर है : बाबूलाल मरांडी

आजाद सिपाही संवाददाता

रांची। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री सह बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सरकार ने 2023-24 के लिए जो बजट पेश किया है, देखने-सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यह बजट राज्य के विकास से कोसों दूर है। राज्य में 60



फीसदी से अधिक लोग खेती पर ही आधारित हैं और 80 फीसदी से

ज्यादा लोग गांवों में रहते हैं। सिंचाई की सुविधा नहीं के बराबर है। आज के बजट में खेती, ग्रामीण विकास और सिंचाई पर कुल बजट का लगभग 12.5 प्रतिशत राशि ही बजटीय उपबंध किया गया है। ऐसे में गांवों और किसानों की हालत कैसे सुधारी जायेगी? यह समझ से परे है।

झारखंड में एक दर्जन से अधिक ठिकानों पर इडी का छापा

कोयला कारोबारी इजहार के घर से मिले तीन करोड़ रुपये

इजहार अंसारी पर निलंबित आइएएस पूजा सिंघल के लिए पैसा वसूलने का आरोप

आजाद सिपाही संवाददाता

हजारीबाग/ कुजू। झारखंड में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की गयी। इडी की टीम ने राजधानी रांची और हजारीबाग में एक साथ 14 ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान हजारीबाग के एक कोयला कारोबारी के यहां से इडी की टीम ने 3 करोड़ रुपये कैश बरामद किये। इडी के अधिकारियों ने इस संबंध में अभी कोई भी विस्तृत जानकारी देने से इंकार किया है। उनका कहना है कि छापे की कार्रवाई खत्म होने के बाद विस्तृत जानकारी दी जायेगी। हजारीबाग में जिस कोयला कारोबारी के ठिकाने से 3 करोड़ रुपये जब्त किये गये हैं, उसका नाम मोहम्मद इजहार अंसारी है। वर्षों से वह कोयला के कारोबार से जुड़ा है। रामगढ़ के बोंगाबाड़ और मांडू में भी उसकी फैक्ट्री है। रामगढ़ में भी इडी ने छापेमारी की। मोहम्मद इजहार हजारीबाग जिला के एक पूर्व विधायक और निलंबित आइएएस अधिकारी पूजा सिंघल का करीबी बताया जाता है।



पूजा सिंघल के करीबी इंजीनियर अशोक कुमार के यहां भी ₹25 करोड़ के कैश के साथ ही बजटीय उपबंध किया गया है। ऐसे में गांवों और किसानों की हालत कैसे सुधारी जायेगी? यह समझ से परे है।

पूजा सिंघल के लिए इजहार पर एकत्र करता था कट मनी बताया जा रहा है कि मोहम्मद इजहार अंसारी कहकशां समूह की कंपनियों का संचालन करता है। उसके नाम पर एक करीब दर्जन शेल कंपनियां चलती हैं। यह भी आरोप है कि इजहार अंसारी खनन विभाग की पूर्व सचिव रहीं पूजा सिंघल के लिए कट मनी एकत्र करता था। पूजा सिंघल को पहले साल मनरेगा घोटाला मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था। पूजा के सीए सुमन कुमार के यहां से 22 करोड़ रुपये जब्त किये थे।



हेमंत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए खोला खजाना

ग्रामीण विकास

बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन मिशन की होगी शुरुआत



आजाद सिपाही संवाददाता

रांची। सरकार ने बजट पर सिंचाई योजना पर भी ध्यान दिया है। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि किसानों को सिंचाई कूप उपलब्ध कराने हेतु मनरेगा तथा राज्य योजना का अभिसरण करते हुए बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन मिशन नामक नयी योजना लागू करने का प्रस्ताव है। इस योजना के अंतर्गत 1 लाख किसानों की व्यक्तिगत भूमि पर सिंचाई कूप का निर्माण कराया जायेगा। इसके लिए राज्य योजना

बजट आकार 8,166 करोड़ रुपये

से प्रति लाभुक 50 हजार रुपये सामग्री मद में तथा शेष राशि मनरेगा योजना से देने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में आय के स्रोतों को बढ़ाते हुए रोजगार सृजन एवं जीवन स्तर को ऊंचा करना हमारा

मुख्य उद्देश्य है। वर्ष 2022-23 में महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत 9 करोड़ अनुमोदित मानवदिवस के विरुद्ध अब तक कुल 7.63 करोड़ मानवदिवस का सृजन किया गया है। वर्ष 2023-24 में भी 9 करोड़ मानव दिवस सृजन करने का लक्ष्य है। इसके लिए 1,260 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है। इसी तरह प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत आगामी वित्तीय वर्ष में 3 हजार 5 सौ 42 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है।

खाद्य सुरक्षा और पेयजल एवं स्वच्छता

जन वितरण प्रणाली दुकान से मोटा आनाज भी मिलेगा

आजाद सिपाही संवाददाता

रांची। राज्य सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 के क्रम में जन वितरण प्रणाली अन्तर्गत मोटा आनाज वितरण किये जाने की योजना तैयार की है। इसके अतिरिक्त प्रोटीनयुक्त अन्य खाद्य सामग्रियों के वितरण भी किया जायेगा। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि हमारी सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि प्रत्येक गरीब को नियमित रूप से ससमय पूरा राशन प्राप्त हो। राज्य के 60 लाख से अधिक परिवारों के 2 करोड़ 60 लाख लाभुकों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। अगले वित्तीय वर्ष में सूचना तकनीक का प्रयोग करते हुए खाद्य वितरण की प्रक्रिया के सुदृढीकरण एवं सरलीकरण का लक्ष्य रखा गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से वंचित रह

बजट आकार खाद्य एवं आपूर्ति 2,750.15 करोड़ रुपये

जाने वाले गरीब तबके को झारखंड खाद्य सुरक्षा योजना के माध्यम से जोड़ा गया है। इसके तहत 4 लाख से अधिक परिवारों के लगभग 20 लाख लाभुकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के सहज खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है।

लोगों को स्वच्छ पेयजल मुहैया कराया जायेगा:

वर्ष 2024 तक जल जीवन मिशन के तहत राज्य के कुल 61 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों

पेयजल एवं स्वच्छता 4,372.21 करोड़ रुपये

को कार्यरत घरेलू नल संयोजन (एफएचटीसी) के द्वारा शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने के लक्ष्य है। इसके विरुद्ध अबतक 18.87 लाख परिवारों को इस योजना से आच्छादित किया जा चुका है। आगामी वित्तीय वर्ष में शत-प्रतिशत उपलब्धि हासिल करने का लक्ष्य है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-11 अंतर्गत ग्राम स्तर पर टोस एवं तरल कचरा प्रबंधन के आधार पर 2,005 गांवों को 1 स्टार, 202 गांवों को 3 स्टार एवं 229 गांवों को 5 स्टार घोषित किया गया है।

मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत 1.40 लाख युवाओं को मिलेगा कौशल प्रशिक्षण

श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास

बजट आकार: 985.85 करोड़ रुपये

आजाद सिपाही संवाददाता रांची। सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष में मुख्यमंत्री सारथी योजना के अंतर्गत राज्य के 1 लाख 40 हजार युवक-युवतियों को कौशल प्रशिक्षण दिये जाने का लक्ष्य रखा है। प्रशिक्षण के उपरांत रोजगार न मिलने की स्थिति में 6 माह तक पुरुषों को 1 हजार रुपये प्रतिमाह तथा महिलाओं और दिव्यांगों को 1 हजार 5 सौ रुपये प्रतिमाह दिया



जायेगा। राज्य के संस्थान काफी जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं। उनके द्वारा काफी पुराने पाठ्यक्रम आधारित शिक्षा दी जा रही है, जिसकी वजह से प्रशिक्षित छात्र-छात्राओं को नौकरी मिलने में कठिनाई होती है। उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त हो, इस

दृष्टिकोण से वर्ष 2023-24 में आइटीआइ संस्थानों के आधारभूत संरचना के सुदृढीकरण, पाठ्यक्रम के उन्नयन तथा नये एवं आधुनिक तकनीकों का उपयोग से बेहतर शिक्षण व्यवस्था उपलब्ध करने का प्रस्ताव बजट में किया गया है।

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा

आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं का मानदेय बढ़ेगा

आजाद सिपाही संवाददाता

रांची। आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं के चयन एवं मानदेय नियमावली गठित की गयी है। इनके मासिक मानदेय में 3,100 से 4800 रुपये की बढ़ोत्तरी की गयी है। वर्ष 2023-24 से इनके मासिक मानदेय में 500 तथा 250 रुपये की वृद्धि की जायेगी। साथ ही इन सबों के लिए 500 रुपये प्रतिवर्ष प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार द्वारा करते हुए उन्हें सामूहिक बीमा योजना से आच्छादित करने का भी बजट में प्रस्ताव किया गया है।

सरकार महिला विकास और सशक्तिकरण की ओर लगातार कदम उठा रही है। इसी क्रम में विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन राशि महिलाओं में स्वच्छता के प्रसार के लिए निःशुल्क सेनेटीरी नैपकीन का वितरण, प्रसव पूर्व गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने एवं प्रसव उपरांत मातृत्व केयर किट वितरण करने के उद्देश्य से महिला एवं किशोरी कल्याण योजना शुरू की जा रही है। सरकार ने सर्वजन पेंशन योजना की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य गरीब जरूरतमंद लोगों तथा अतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को आर्थिक सहायता पहुंचाना है। इस योजना के अंतर्गत लगभग 11 लाख नये लाभुकों को जोड़ते हुए अब तक 21 लाख 8 हजार लाभुकों को आच्छादित किया गया है। इस योजना को आगामी वर्ष भी चालू रखा जायेगा। इसके लिए वर्ष 2023-24 में 2.131 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। आंगनबाड़ी केंद्र में आनेवाले बच्चों को पाठशाला पूर्व शिक्षा के

बजट आकार 7,171 करोड़ रुपये



खास बातें:

- राज्य में आंगनबाड़ी केंद्रों का अपना भवन नहीं रहने से काफी दिक्कतें आती हैं। इसके मद्देनजर 800 नये आंगनबाड़ी भवन के निर्माण होगा। इसके तहत आगामी वित्तीय वर्ष में 100 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है।
- राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को 6 हजार रुपये प्रति केंद्र की दर से समेकित निधि उपलब्ध करायी जायेगी, ताकि छोटी-छोटी तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके।
- आंगनबाड़ी सेविकाओं को आधुनिक सूचना तंत्र से जोड़ने के उद्देश्य से सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं को स्मार्ट फोन उपलब्ध कराया जायेगा।

लिए 'आंगनबाड़ी चलो अभियान योजना' प्रारंभ की जायेगी। इस योजना के तहत बच्चों को पोशाक एवं वकबुक तथा सभी केंद्रों में फर्नीचर इत्यादि उपलब्ध कराये जाने 190 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

जल संसाधन और पंचायती राज

पटमदा और पलामू में मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजनाएं होंगी शुरू



आजाद सिपाही संवाददाता

रांची। सोन कनहर मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना में भू-अर्जन प्रक्रिया की जटिलता से बचते हुए तथा इसके तीव्र कार्यान्वयन के मद्देनजर दुमका में मसलिया - रानेश्वर एवं देवघर जामताड़ा जिला में सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजनायें कार्यान्वित की जा रही हैं। इसी आधार पर आगामी वित्तीय वर्ष में पटमदा तथा पलामू मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना की योजना है। इसके लिए बजट में प्रावधान किया गया है।

पंचायत सचिवालय होंगे सुदृढ़:

आम लोगों को पंचायत स्तर पर सभी सुविधायें एक छत के नीचे उपलब्ध कराने का सरकार प्रयास कर रही है। इसके लिए सरकार ने आगामी बजट में पंचायत सचिवालय सुदृढीकरण योजना शुरू करने का प्रस्ताव है। सभी

बजट आकार जल संसाधन 1,964 करोड़ रुपये

पंचायत सचिवालयों में पंचायत कार्यालय के अतिरिक्त प्रजा केंद्र के माध्यम से सभी प्रकार के प्रमाण पत्र ऑनलाइन सुविधायें, बैंकिंग कोरेस्पॉण्डेंट से संबंधित सुविधायें निर्धारित दिवस पर हल्का से संबंधित कार्य की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त ग्रामीणों के सामान्य पठन-पाठन हेतु प्रत्येक पंचायत सचिवालय में चरणबद्ध तरीके से पंचायत ज्ञान केंद्र की स्थापना की जायेगी। पंचायत सचिवालयों का जिला एवं राज्य स्तर से संवाद स्थापित करने तथा सरकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार हेतु 65 ईंच का एलईडी टीवी लगाये जायेंगे।

पंचायती राज 1.968 करोड़ रुपये

15वें वित्त आयोग की राशि ग्राम पंचायतों तक जायेगी:

15वें वित्त आयोग अनुदान मद में 1,307 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त होने की संभावना है, जिसमें से जिला परिषदों, को 10 प्रतिशत, पंचायत समितियों को 15 प्रतिशत तथा ग्राम पंचायतों को 75 प्रतिशत राशि दी जायेगी। उक्त राशि से संबंधित निस्वरीय संस्थाओं द्वारा 30 प्रतिशत जलापूर्ति पर 30 प्रतिशत स्वच्छता पर और शेष 40 प्रतिशत का व्यवस्थानीय आवश्यकता आधारित योजनाओं पर किया जा सकेगा। इससे पंचायत स्तर पर आधारभूत संरचना की गंभीर खाई को पूरा किया जा सकेगा।

फसल सुरक्षा कार्यक्रम की होगी शुरुआत

कृषि एवं संबद्ध प्रक्षेत्र

बजट आकार 4,627 करोड़ रुपये

योजना के माध्यम से 45 लाख से अधिक किसानों के बीच 1 हजार 7 सौ 27 करोड़ रुपये की ऋण माफी की गयी। सुखाड़ राहत हेतु प्रत्येक किसान परिवार को 3,500 रुपये की दर से लगभग 13 लाख किसानों के खाते में 461 करोड़ रुपये अनुग्राहिक राशि हस्तांतरित की गयी। इन दोनों योजनाओं के

मुख्य बातें:

- वर्ष 2023-24 में 5 एकड़ से कम क्षेत्र वाले तालाबों का मशीन से गाद हटाने तथा डीप वॉरिंग इत्यादि योजना हेतु 500 करोड़ रुपये का प्रस्ताव।
- सौर ऊर्जा आधारित माइक्रोलिफ्ट इरिगेशन सिंचाई की व्यवस्था को कारगर बनाने में काफी

लाभ से अब तक वंचित किसानों को वित्तीय वर्ष 2023-24 में लाभान्वित किया जायेगा।

वर्ष 2023-24 में कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ) एफपीओ के अनुदान मद में 50 करोड़ रुपये प्रस्तावित। राज्य सरकार द्वारा मिलेट उत्पादन को अधिकाधिक प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से झारखंड राज्य मिलेट मिशन प्रारंभ किया जायेगा, जिसके लिए 50 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत अधिक से अधिक लाभुकों को जोड़ने हेतु

किफायती है। इसकी उपयोगिता को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में कृषि समृद्धि योजना लागू की जायेगी।

- वर्ष 2023-24 में कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ) एफपीओ के अनुदान मद में 50 करोड़ रुपये प्रस्तावित।
- राज्य सरकार द्वारा मिलेट उत्पादन को अधिकाधिक प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से झारखंड राज्य मिलेट मिशन प्रारंभ किया जायेगा, जिसके लिए 50 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे।
- मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत अधिक से अधिक लाभुकों को जोड़ने हेतु

300 करोड़ रुपये का बजटीय उपबंध किया गया है।

- गिरिडीह एवं जमशेदपुर में नये डेयरी प्लांट तथा रांची में मिल्क पाउडर प्लांट एवं मिल्क प्रोडक्ट प्लांट की स्थापना हेतु 180 करोड़ रुपये का प्रस्ताव।
- दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन राशि 2 रुपये से बढ़ाकर 3 रुपये करने की घोषणा।
- लैम्पस / पैक्स के भंडारण क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से वर्ष 2023-24 में 100 एमटी क्षमता के कुल 566 एवं 500 एमटी क्षमता के 146 नये गोदामों का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है।

मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत 1.40 लाख युवाओं को मिलेगा कौशल प्रशिक्षण

बोकारो और रांची में मेडिकल कॉलेज

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण

बजट आकार: 7,040.90 करोड़ रुपये

कॉलेज की स्थापना की घोषणा की गयी है। वहीं, पलामू, चाईबासा एवं दुमका में मनोचिकित्सा केंद्र की स्थापना की जायेगी। मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि स्वस्थ व्यक्ति से स्वस्थ समाज, स्वस्थ समाज से विकसित राज्य की अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार राज्य के सभी नागरिकों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों को हर प्रकार

मुख्य बातें:

- बोकारो एवं रांची में मेडिकल कॉलेज की स्थापना।
- पलामू, चाईबासा एवं दुमका में मनोचिकित्सा केंद्र की स्थापना।
- रांची में पीपीपी मोड पर अल्कोहल नशा विमुक्ति केंद्र खोला जाना।
- चलंत ग्राम क्लीनिक का संचालन एवं प्रबंधन।
- नये नर्सिंग कॉलेज एवं फार्मसी कॉलेज की स्थापना।

की स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्पित है।

वन उत्पादों के प्रसंस्करण इकाइयों को प्रोत्साहित किया जायेगा

बजट आकार: 1162.70 करोड़ रुपये

आजाद सिपाही संवाददाता रांची। सरकार ने बजट में वर्ष 2023-24 में लघु वन उत्पादों के प्रसंस्करण इकाइयों को प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव है। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि आजादी के 75 वर्ष बाद भी काफी संख्या में ऐसे गांव हैं, जो जंगल के बीच-बीच अवस्थित हैं तथा अभी तक पक्की सड़क से नहीं जुड़े हैं। राज्य सरकार इन सभी गांवों को आगामी वित्तीय वर्षों में पक्की सड़क से जोड़ने का कार्य करेगी।

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन



फोकस : अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण

मानकी, मुंडा, डकुआ को दुपहिया वाहन देगी सरकार

बजट आकार 3011.65 करोड़ रुपये

आजाद सिपाही संवाददाता रांची। सरकार ने बजट में मानकी-मुंडा शासन व्यवस्था के तहत मानकी, मुंडा, डकुआ आदि की न्यायिक, प्रशासनिक एवं वित्तीय कार्य भूमिकाओं के महत्व को देखते हुए दोपहिया वाहन सुलभ बनाने की योजना तैयार की है।

छात्रवृत्ति की राशि में लगभग तीन गुणा वृद्धि की



मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना (सीएमएजोपी) के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए...

मुख्य बातें:

- अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं को अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ नि:शुल्क आवासन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग, धनबाद, देवघर, बोकारो, चाईबासा आदि प्रमुख शहरों में चरणबद्ध तरीके से बहुमंजिला छात्रावासों के निर्माण कराने की घोषणा बजट में की गयी है।

पथ निर्माण

रांची में इनर रिंग रोड के मिसिंग लिंक का निर्माण



आजाद सिपाही संवाददाता रांची। वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने पथ निर्माण विभाग के बजट के बारे में कहा कि आधारभूत संरचना का विकास न केवल अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करता है, वरन यह सामाजिक विकास और सांस्कृतिक उन्नयन का भी वाहक है।

नगर विकास एवं आवास

शहरी जलापूर्ति योजनाओं के निर्माण पर जोर

बजट आवंटन : 3346.37 करोड़ रुपये

आजाद सिपाही संवाददाता रांची। नगर विकास विभाग के बजट पर वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने कहा कि स्वच्छ सर्वेक्षण, 2022 में स्वच्छता कार्यों हेतु देश के समस्त राज्यों में से झारखंड राज्य को (सौ निकायों से कम वाले राज्य की श्रेणी में) द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है तथा बुंदू एवं चाइबासा को फीडबैक श्रेणी में सम्मानित किया गया है।



प्रस्ताव है। एशियन विकास बैंक द्वारा संचालित योजना अंतर्गत वर्ष 2023-24 में झुमरीतिलैया शहरी जलापूर्ति योजना, मेदिनीनगर शहरी जलापूर्ति योजना एवं रांची इन्टेक वर्क्स का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जायेगा।

13 लाख उपभोक्ताओं को स्मार्ट प्रीपेड मीटर की सुविधा

बजट आवंटन : 7769.10 करोड़ रुपये

ऊर्जा विभाग



(आरडीएसएस) के तहत राज्य सरकार के पावर लॉस को कम करने एवं वितरण व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए पुराने तार को एवी केबुल से बदलने, नये पावर सब स्टेशन बनाने, पुराने ट्रांसफार्मर को बदलने और नया लगाने के साथ-साथ लगभग 13 लाख उपभोक्ताओं को स्मार्ट प्रीपेड मीटर युक्त करने की योजना प्रस्तावित है।

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन

चक्रधरपुर और चांडिल में उप कारा का निर्माण होगा

रांची (आजाद सिपाही)। वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने कहा कि राज्य के सभी जिलों में अवैध पुलिस लाइन का नश्वर सुदृढीकरण किये जाने की योजना है। इसके तहत पुलिस प्रशिक्षण केंद्र, मुसाबनी, जामताड़ा एवं पाकुड़ पुलिस लाइन में त्वाटर निर्माण, गोड्डा पुलिस लाइन में रिजर्व ऑफिस, त्वाटर परे ग्राउंड आदि के निर्माण का प्रस्ताव है।

बजट आवंटन : 9158.25 करोड़ रुपये

निर्माण प्रस्तावित है। मानवीय न्यायालय में राज्य काराओं के बंदियों के उपस्थापन / विचारण हेतु विभिन्न काराओं / संबन्धित व्यवहार न्यायालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम का अधिष्ठापन कराया जाना प्रस्तावित है।

पुराने औद्योगिक क्षेत्रों का होगा पुनर्निर्माण

बजट आवंटन : 474.50 करोड़ रुपये

उद्योग विभाग



रांची। वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने उद्योग विभाग के बजट के बारे में कहा कि पुराने औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत संरचना काफी जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है, जिसका कुप्रभाव औद्योगिक इकाइयों का स्थापना की संभावनाओं को देखते हुए नये औद्योगिक क्षेत्र के निर्माण का भी प्रस्ताव है।

हेमंत सोरेन सरकार का हमर अपन बजट लोक कल्याणकारी बजट : सुप्रियो

रांची (आजाद सिपाही)। झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार का हमर अपन बजट लोक कल्याणकारी बजट है। उन्होंने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता आम लोगों की बुनियादी चीजें स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, कल्याण, ऊर्जा, पर्यटन को सर्वांगीण रखा गया है।



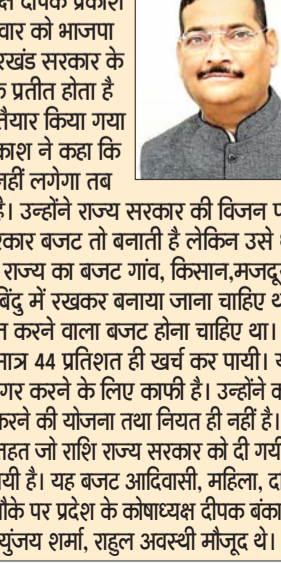
झारखंड राज्य को तेज गति से विकास देने वाला यह बजट है : राजेश ठाकुर

रांची (आजाद सिपाही)। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य को तेज गति से विकास देने वाला यह बजट है। यह गांव, गरीब, मजदूर, किसान, नौजवान को ध्यान में रख कर बनाया गया बजट है।



झारखंड सरकार कर बजट हमीन कर बजट नहीं बल्कि लूट कर बजट है: दीपक प्रकाश

रांची (आजाद सिपाही)। झारखंड सरकार के द्वारा पेश किए गये बजट को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने लूट का बजट कहा। श्री प्रकाश शुकवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रेस से कहा कि झारखंड सरकार के इस बजट का अवलोकन करने से साफ प्रतीत होता है।



राज्य सरकार बजट के नाम पर बस खानापूर्ति कर रही है: सुदेश महतो

रांची (आजाद सिपाही)। राज्य सरकार द्वारा पेश किये गये बजट को लेकर झारखंड के पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं आजूस पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने झूठ का पुलिंदा बताया। उन्होंने कहा कि बजट में बुनियादी सवालों को दरकिनारा किया गया।



होली और शब-ए-बारात त्योहार को लेकर विभिन्न थानों में हुई शांति समिति की बैठक एक-दूसरे की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाएं: अमित सोनी



सतबरवा थाने में आयोजित शांति समिति की बैठक में उपस्थित लोग।

आजाद सिपाही संवाददाता
सतबरवा/पलामू। होली और शब-ए-बारात त्योहार को लेकर शुक्रवार को सतबरवा थाना परिसर में शांति समिति की बैठक हुई। जिसकी अध्यक्षता बीडीओ राज किशोर प्रसाद एवं संचालन थाना प्रभारी अमित सोनी ने किया। बैठक में थाना क्षेत्र के सभी गणमान्य एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। इस दौरान सभी लोगों ने कहा कि सतबरवा में हमेशा शांतिपूर्ण होली मनाती आ रही है। इस बार भी हम सब हिंदू मुसलमान मिलकर होली मनाएंगे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए

बीडीओ राज किशोर प्रसाद ने कहा कि होली खुशी और भाईचारे का त्योहार है। इसे मिलजुल कर मनाएं और किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें। वहीं, थाना प्रभारी अमित सोनी ने कहा कि होली खुशियों का त्योहार है। इसमें पुरानी से पुरानी दुश्मनी भी भूला कर एक दूसरे को गले लगाते हैं। साथ ही शब-ए-बारात में मुसलमान भाई नमाज पढ़ते हैं और कब्रिस्तान को रोशनी से जगमगाते हैं। इसलिए सभी लोगों से अपील है कि एक-दूसरे की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाएं और शांतिपूर्ण अपना-अपना त्योहार

हर परस्थिति से निपटने के लिए तैयार : बीडीओ

आजाद सिपाही संवाददाता

हरिहरगंज/पलामू। हरिहरगंज थाना परिसर में शुक्रवार को होली व शब-ए-बारात पर्व एक साथ होने के कारण शांति समिति की बैठक में पुलिस-प्रशासनिक अधिकारियों ने आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। साथ ही सभी से शांति और आपसी सौहार्द के साथ पर्व मनाने की अपील की गई। बैठक की अध्यक्षता बीडीओ जयप्रकाश नारायण और संचालन प्रभारी थाना प्रभारी निर्भय कुमार ने किया। बैठक के दौरान बीडीओ जयप्रकाश नारायण व थाना प्रभारी निर्भय कुमार ने कहा कि हमारा प्रयास है कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था को कायम रखते हुए पर्व को



मनाया जाए। उपद्रव करने वालों पर प्रशासन की पैनी नजर रहेगी। साथ ही गश्ती दल विभिन्न क्षेत्रों में गश्त करती नजर आएगी। पुलिस-प्रशासन हर परिस्थिति से निपटने को तैयार है। वहीं, बैठक के बाद एक-दूसरे को अबीर लगाकर होली की बधाई दी गई। इस मौके पर एसआई शिवशंकर उरांव, रामेश्वर तिवारी, महावीर एक्का, अनूप कुमार, रंजीत कुमार, सांसद प्रतिनिधि अरुण

मनाए। इस मौके पर भाजा अनुसूचित जनजाति के प्रदेश उपाध्यक्ष अवधेश सिंह चेतो,

विधायक प्रतिनिधि राणा प्रताप कुशवाहा, सामाजिक कार्यकर्ता आशीष सिन्हा, प्रमोद यादव, रवि

मिश्रा, युवा समाजसेवी राजीव रंजन, वैश्य जागृति मंच के अध्यक्ष भोला गुप्ता, अतहर हुसैन, शशि गुप्ता, राजद प्रखंड अध्यक्ष महेंद्र यादव, बुधन सिंह यादव, महादेव यादव, एनसीपी नेता अजय सिंह, इरफान शाहिद, महताब शाहिल उर्फ बबलू, दीपक कुमार, उदय सिंह, काग्रेस नेता कृष्ण कुमार सिंह, अरविंद पासवान, इफतेखार अहमद नूरी, भीमसेन शर्मा, मुस्लिम अंसारी, अमित कुमार सिंह, मनोज मेहता, गोपाल प्रसाद, सत्येंद्र भुईयां, करण राजवीर, पम्मीलाल सिन्हा, रामजी पासवान, पंसेन शौलू सिंह, राजकुमार पासवान, सत्येंद्र पासवान आदि उपस्थित थे।

प्रसाद, दीपक चंद्रवंशी, बाबर अंसारी, मोहम्मद मियां, मोहम्मद शकीन आदि उपस्थित थे।

शहर के लोगों को मिलेगी बेहतर चिकित्सा सुविधा : नगर अध्यक्ष



शहरी स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास करते नगर अध्यक्ष व अन्य।

नगर अध्यक्ष व उपाध्यक्ष ने किया शहरी स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास
आजाद सिपाही संवाददाता
हुसैनाबाद। नगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड-1 में चर्च के समीप सामूदायिक भवन को शहरी स्वास्थ्य केंद्र में उद्घाटित करने के कार्य का शिलान्यास किया गया। शुक्रवार को नगर पंचायत अध्यक्ष शशि कुमार, नगर उपाध्यक्ष गयासुद्दीन सिद्दीकी, वार्ड पार्षद अखिलेश यादव, सिटी मैनेजर नजीबुल्लाह अंसारी आदि ने संयुक्त रूप से नारियल फोड़कर शिलान्यास किया। नगर अध्यक्ष शशि कुमार ने कहा कि शहर के लोगों को सड़क, नाली, शुद्ध पेयजल व स्वच्छता के साथ ही

बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिले इस उद्देश्य के साथ ही शहरी स्वास्थ्य केंद्र बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शहर के लोगों को आबादी के अनुपात में चिकित्सा सुविधा मिले इसका प्रयास किया जा रहा है। इस शहरी स्वास्थ्य केंद्र का कार्य पूर्ण होने पर डॉक्टरों व नर्सों की पदस्थापना होगी। वहीं, नगर उपाध्यक्ष गयासुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि नगर पंचायत वाशियों को सुलभ रूप से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना हम सभी की प्राथमिकता है। इस मौके पर अखिलेश पासवान, अमेंद्र ठाकुर, अलीम अंसारी और प्रसाद यादव आदि मौजूद थे।

आपसी प्रेम और भाईचारे का पर्व है होली : ऋषभ गर्ग

आजाद सिपाही संवाददाता
मेदिनीनगर। संत मरियम स्कूल के आयोजित कार्यक्रम में रंगोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि में सदर एसडीपीओ ऋषभ गर्ग के अलावा विश्रामपुर एसडीपीओ सुरजीत कुमार, सदर एसडीओ राजेश शाह, चव्वसाई संघ के अध्यक्ष प्रभात अग्रवाल और स्कूल के चेयरमैन अविनाश देव ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्य अतिथि ऋषभ गर्ग ने कहा कि होली का त्योहार आपसी प्रेम और भाईचारे को बढ़ावा देता है। उन्होंने कहा कि हर एक पर्व हमें कुछ न कुछ शिक्षा देकर जाती है। हम सभी को यह प्रयास करना चाहिए की आने वाली होली में अपने अंदर के छल, प्रपंच,



अधम का नाश कर अच्छे मार्ग को अपनाएं ताकि भविष्य बेहतर हो। वहीं, सुरजीत कुमार ने सभी को होली की अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हम सब अपने बेहतर कर्मों से यह प्रयास करे कि आगामी रंगों का त्योहार होली हम सभी के जीवन में उत्सव समृद्धि और सुख का नया रंग उड़ले। सदर एसडीओ राजेश शाह ने कहा कि धर्म और सत्य पर आधारित यह पर्व हम सभी को अनेक मार्ग प्रदत्त करता है।

बुराई पर अच्छाई के प्रतिक का यह पर्व हमें सदैव सत्य के साथ अडिग रहने की प्रेरणा देता है। संत मरियम स्कूल के चेयरमैन अविनाश देव ने कहा कि आप सभी बच्चे होली की छुट्टियां मनाने घर जा रहे हैं। आप सभी छुट्टियों का आनंद लें पर अपने स्वाध्याय को चालू रखें। नियमबद्ध होकर घर में भी अनुशासन का पालन करें और अपने समाज को बेहतर विद्यार्थी के रूप में अपना परिचय दें।

किसी तरह की अफवाहों पर ना दें ध्यान: एसडीपीओ



होली व शब-ए-बारात में सुरक्षा की तैयारियों को लेकर हुसैनाबाद में शांति समिति की बैठक

आजाद सिपाही संवाददाता
हुसैनाबाद। थाना परिसर में शुक्रवार को होली व शब-ए-बारात के दौरान सुरक्षा तैयारियों को लेकर शांति समिति की बैठक हुई। जिसमें शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में सभी त्योहार मनाने का निर्णय लिया गया। बैठक में प्रशासनिक पदाधिकारियों के अलावे क्षेत्र के स्थानीय प्रतिनिधि और प्रबुद्धजनों ने हिस्सा लिया। बैठक में एसडीओ कमलेश्वर नारायण ने सभी लोगों से होली और शब-ए-बारात की शुभकामना देते हुए अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की। दोनों समुदाय के लोगों से होली व शब-ए-बारात में आपसी भाईचारेगी के साथ मनाने को कहा। एसडीपीओ पूज्य प्रकाश ने क्षेत्र में होने वाले होलिका दहन की जानकारी लेते

हुए विधि व्यवस्था को ले आवश्यक दिशा निर्देश दिया। उन्होंने सभी लोगों से मिलजुल कर समाज में प्यार का संदेश देने की बात कही। उन्होंने असमाजिक तत्वों पर नजर रखने और किसी भी अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की बात अपील की। अंत में सभी ने एक-दूसरे को अबीर लगाकर होली की शुभकामना दी। इस मौके पर जप उपाध्यक्ष आलोक कुमार सिंह, झामुमो के वरीय नेता एजाज हुसैन उर्फ छेदी खान, चंद्रेश्वर प्रसाद, समाजसेवी अब्बास अंसारी, सीओ नंद कुमार राम, महिला थाना प्रभारी सूर्यबाला भुंगराज, नप उपाध्यक्ष गयासुद्दीन सिद्दीकी, आलोक केशरी, पूर्व नप अध्यक्ष उषा देवी, रामेश्वर राम, वार्ड पार्षद नजीर अहमद, सुहेल आलम, अखिलेश यादव, अर्जुन प्रसाद गुप्ता, जीशन हसन, तवकी हुसैन रिजवी, एसआई सौरव कुमार और शैलेंद्र सिंह आदि उपस्थित थे।

बजट निराशा पूर्ण : आनंद शंकर

इस बजट से राज्य का विकास कभी नहीं हो सकता : डिपल
आजाद सिपाही संवाददाता

मेदिनीनगर। झारखंड सरकार द्वारा शुक्रवार को पेश किया गया बजट निराशाजनक रहा। पूरे बजट में तथ्यों से परे वादों को ही बल दिया गया है। यह हेमंत सरकार का आखिरी पूर्ण बजट था इसलिए इसमें आकाश कुसुम जैसे कई वादे किए गए, जिसका धरातल पर कोई महत्व नहीं है आज जब पूरा राज्य लगभग व्यवसाय हीन हो चुका है उस समय व्यवसायिक समस्याओं पर कुछ भी न बोलना और अपने वादों के अनुरूप कृषि कर को खत्म न करना यह सरकार की दोहरे चरित्र को दर्शा रहा है। पलामू चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष आनंद शंकर ने कहा कि यह सरकार पूर्ण रूप से विफल हो चुकी है। जिसका ताजा उदाहरण रामगढ़ उप चुनाव में दिखा है। सचिव इंद्रजीत सिंह डिंपल ने पलामू में मनोचिकित्सक डॉक्टरों की नियुक्ति एवं मनो चिकित्सालय खोलने के कदम का स्वागत किया और कहा कि अगर सरकार अब ईमानदारी से



काम करें तो निश्चित तौर पर झारखंड पुनः पटरी पर लौट सकता। सरकार खोखले वादों के विपरित कोई काम भी बिना भ्रष्टाचार के पूर्ण नहीं हो पा रहा है। आज के बजट भाषण में खुद वित्त मंत्री एवं मुख्यमंत्री थके-थके से और अस्तुष्टि दिखे। वित्त एवं मुख्यमंत्री ने भाषण पर प्रक्रिया भी उत्साह पूर्वक नहीं था। पलामू चेंबर ऑफ कॉमर्स इस संपूर्ण बजट को अनुपयोगी बताते हुए इससे 10 में से 4 अंक देता है। इस बजट को राज हित में कदापि नहीं कहा जा सकता हमें सरकार से ज्यादा आशा थी जो कि पूरी नहीं हो सकी।

किसी भी विभाग की एक योजना के लिए हो एक खाते का इस्तेमाल : डीसी

आजाद सिपाही संवाददाता
मेदिनीनगर। पलामू डीसी आंजनेयुलु वेडु और डीडीसी रवि आनंद ने शुक्रवार को जिले के सभी सीओ और बीडीओ के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। डीसी ने सभी पदाधिकारियों को सरकार के सभी विभागों में एक योजना के लिए एक खाता का इस्तेमाल करने और बाकि सभी खातों से शेष राशि



बीडीओ कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिले के पदाधिकारियों से वार्ता करते डीसी।

सरकार को वापस एक सप्ताह के अंदर भेजने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव का स्पष्ट निर्देश है कि सभी विभाग को एक योजना के लिए एक खाते का इस्तेमाल करना है। बाकी सभी खातों में बचे राशि को सरकार को वापस ट्रांसफर करना है। डीसी ने बताया कि जिले के सभी प्रखंडों को मिलाकर कुल 19 करोड़ रुपये की राशि राज्य सरकार को वापस भेजना है।

स्पोर्ट्स

23 दिन में 5 टीमों खेलेंगी 20 लीग मैच, पहला मुकाबला गुजरात जाइंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच विमेंस प्रीमियर लीग के पहले सीजन का आगाज आज से

एजेसी
नई दिल्ली। विमेंस प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) के पहले सीजन का आगाज शनिवार से होने जा रहा है। 23 दिन तक चलने वाली इस लीग में पांच टीमों 20 लीग और दो नॉकआउट मैच खेलेंगी। टूर्नामेंट की शुरुआत शनिवार शाम 7.30 बजे डीवाई पाटिल स्टेडियम में गुजरात जायंट्स और मुंबई इंडियंस के मैच के साथ होगी। प्रतियोगिता के सभी 22 मैच मुंबई के डीवाई पाटिल और ब्रेबोर्न स्टेडियम पर खेले जाएंगे। मेग लेनिंग की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स की टीम सबसे संतुलित और मजबूत नजर आ रही है।



जबकि, मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलूरु की प्लेइंग-11 थोड़ी कमजोर है।
कौन-कौन सी टीमों खेल रही हैं?
विमेंस प्रीमियर लीग के पहले सीजन में 5 टीमों खेलती नजर आएंगी। इनमें दिल्ली कैपिटल्स, मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलूरु, गुजरात जायंट्स और

यूपी वॉरियर्स शामिल हैं। दिल्ली की कप्तान मेग लेनिंग हैं। वहीं, मुंबई की हरमनप्रीत कौर, बेंगलूरु की स्मृति मंधाना, गुजरात की बेथ मूनी और यूपी की एलिसा हीली हैं। इस तरह 3 टीमों की कप्तान ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के पास है, जबकि दो की कप्तान भारतीय खिलाड़ियों को मिली हैं।
एक टीम कितने मैच खेलेंगी?
4 से 21 मार्च तक लीग स्टेज के 20 मैच होंगे। पुरुष आईपीएल के शुरूआती सीजन की तरह यहां भी हर टीम एक-दूसरे से 2-2 मैच खेलेंगी। इस तरह हर टीम लीग स्टेज में कम से कम 8 मैच

खेलेंगी। 20 लीग मैचों के बाद पाइंट्स टेबल में पहले स्थान पर रहने वाली टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी। वहीं, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाली टीमों के बीच 24 मार्च को एलिमिनेटर मुकाबला होगा। हारने वाली टीम तीसरे स्थान पर फिनिश रहेगी और जीतने वाली टीम 26 मार्च को ब्रेबोर्न स्टेडियम में होने वाला फाइनल खेलेंगी।
22 मैचों के बाद मिलेगा पहला विनर
लीग स्टेज के 20 मुकाबले और क्वालिफायर के 2 मैच समेत

टूर्नामेंट में कुल 22 मैच होंगे। इसके बाद डब्ल्यूपीएल का पहला चैंपियन मिलेगा। बताते चलें कि 17 दिन में टूर्नामेंट के 20 लीग मैच होंगे। 5, 18, 20 और 21 मार्च को 4 डबल हेडर होंगे, यानी एक ही दिन में 2 मुकाबले होंगे। पहला मैच दोपहर को 3.30 बजे और दूसरा शाम 7.30 बजे से शुरू होगा। इन 4 दिनों के अलावा सभी मैच शाम 7.30 बजे से ही शुरू होंगे। एलिमिनेटर और फाइनल मुकाबला भी शाम 7.30 बजे से ही खेला जाएगा। 17 और 19 मार्च को रेस्ट दे रहेगे, क्योंकि इस दिन भारत-ऑस्ट्रेलिया की पुरुष टीमों के बीच भारत में वनडे

सीरीज के मुकाबले होंगे। दर्शक दोनों ही जगह समय दे सकें, इसलिए इस दिन विमेंस प्रीमियर लीग के मैच नहीं रखे गए।
दिल्ली कैपिटल्स सबसे संतुलित टीम
ऑस्ट्रेलिया की मेग लेनिंग को टीम की कप्तान बनाया गया है। जेमिमा रोड्रिगज उप कप्तान हैं और टीम में शेफाली वर्मा, मारियन कैप, एलसन कैप्पी, जेस जोनासेन, राधा यादव और शिखा पांडे जैसी टॉप क्लास इंटरनेशनल प्लेयर हैं।

इंदौर की पिच को आइसीसी ने बताया 'खराब', काटे गये 3 डिमेरिट पाइंट्स

नई दिल्ली (एजेसी)। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला गया तीसरा टेस्ट तीसरे दिन ही खत्म हो गया। 15 सेशन का खेल 7 सेशन ही चल सका। मैच में 31 विकेट गिरे, जिनमें से 26 स्पिनर्स ने लिए। जिसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आइसीसी) ने स्टेडियम की पिच को 'पुअर' यानी खराब रेटिंग दी है।
3 डिमेरिट पाइंट्स काटे
मैच के पहले ओवर में पांचवीं बॉल से ही पिच उखड़ने लग गई थी। मैच रेफरी क्रिस ब्रोड ने भी बताया कि पिच पहले दिन से उखड़ने लगी और लगातार खराब होती चली गई। आइसीसी के मैच

रेफरी ने पिच को खराब रेटिंग दी। साथ ही होलकर स्टेडियम को 3 डिमेरिट पाइंट भी दिए गए। ब्रोड ने कहा कि पिच बहुत सूखा था। स्पिनर्स को बहुत ज्यादा मदद थी, इस पर बैटर और बॉलर के बीच बराबरी का मुकाबला नहीं हुआ।
14 दिन में अपील कर सकता है बीसीसीआइ
आइसीसी द्वारा पिच को खराब रेटिंग मिलने के बाद अब बीसीसीआइ के पास 14 दिन का समय है। इतक 14 दिन में रेटिंग के खिलाफ अपील कर सकता है। अगर अपील नहीं की गई तो स्टेडियम पर 3 डिमेरिट पाइंट्स बने रहेंगे।

